

प्रेस रिलीज

पेट्रोल और डीजल पर बीआईएस बीएस VI ईंधन मानदंडों को शामिल करते हुए बीआईएस द्वारा भारतीय मानकों का पुनरीक्षण

भारतीय मानक ब्यूरो (भा.मा.ब्यूरो) ने पेट्रोल (आई एस 2796) और डीजल (आई एस 1460) पर भारतीय मानक पुनरीक्षित किए हैं। अब तक इन मानकों ने बीएस IV तक उत्सर्जन मानदंडों पर आधारित ईंधन की अपेक्षाओं को उल्लेखित किया गया था।

सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ प्रदूषण को कम करने के लिए दिनांक 01 अप्रैल 2018 से दिल्ली एनसीआर में बीएस VI उत्सर्जन मानदंडों को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। देश के बाकी हिस्सों में यह 01 अप्रैल 2020 से कार्यान्वित होगा।

भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय होने के नाते भारतीय मानक ब्यूरो ने तदनुसार बीएस VI ईंधन-विशिष्टताओं को शामिल करते हुए पेट्रोल और डीजल के मानकों को पुनरीक्षित किया है।

पुनरीक्षित मानक से सल्फर की मात्रा कम होने के कारण पर्यावरण में सुधार होगा एवं सांस संबंधी समस्याओं में भी कमी आएगी और इससे नाइट्रोजन आक्साइड (एनओएक्स) के उत्सर्जन में भी कमी आएगी।

ये मानक पेट्रोल में इथेनॉल और डीजल में बायो-डीजल मिश्रण बढ़ाने की अनुमति भी देते हैं। जो कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करने में मददगार साबित होंगे और इससे कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी।

Press Release

BIS revises Indian Standards on petrol and diesel incorporating BSVI fuel norms

BIS has revised the Indian Standards on Petrol (IS 2796) and Diesel (IS 1460) So far, these standards covered fuel requirements based on emission norms upto BS IV.

With a view to conserve natural resources as well as to reduce pollution, Government has decided to implement BS VI emission norms in Delhi NCR from 1 April 2018. In rest of the country these will be implemented from 1 April 2020.

Accordingly, BIS being the National Standards Body of India, revised these standards on Petrol and Diesel incorporating BS VI fuel specifications,

The revised standards will improve the environment and reduce respiratory problems due to reduction in permissible sulphur content which will also reduce emission of nitrogen oxides (NOX).

These standards also permit increased blending of Ethanol in Petrol and Bio-diesel in Diesel which will help in conservation of natural resources and reduction in import of Crude.